

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 सितम्बर 2015—भाद्र 23, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्र. 4630-282-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 अगस्त, 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०१५

मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, २०१५

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
२. परिभाषाएं.
३. बल का गठन.
४. पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति तथा शक्तियां.
५. बल के नामांकित सदस्यों की नियुक्ति.
६. बल के सदस्यों के प्रमाण-पत्र.
७. बल का अधीक्षण तथा प्रशासन.
८. बल के सदस्यों के कर्तव्य.
९. बल का परिनियोजन.
१०. वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति.
११. वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति.
१२. गिरफ्तारी के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.
१३. औद्योगिक स्थापनों को तकनीकी परामर्शी सेवाएं देने का उपबंध.
१४. औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों को पुलिस अधिकारियों के समान विशेषाधिकार तथा दायित्वों का होना.
१५. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१६. अपराधों का संज्ञान.
१७. बल के सदस्यों को सदैव कर्तव्य पर समझा जाना तथा राज्य में तथा राज्य के बाहर भी नियोजित किया जा सकना.
१८. दण्ड और अपीलें.
१९. संगम इत्यादि बनाने के अधिकार के विषय में निर्बंधन.
२०. निलंबन के दौरान बल के सदस्यों के उत्तरदायित्व.
२१. बल का सदस्य न रह गए व्यक्तियों द्वारा प्रमाण-पत्र, आयुध आदि का अभ्यर्पण.
२२. १९२२ के अधिनियम क्रमांक २२ का बल के सदस्यों को लागू होना.
२३. कतिपय अधिनियमों का बल के सदस्यों पर लागू न होना.
२४. नियम बनाने की शक्ति.
२५. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०१५

मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, २०१५

[दिनांक २४ अगस्त, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १४ सितम्बर, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

औद्योगिक स्थापनाओं, औद्योगिक उपक्रमों, निजी औद्योगिक उपक्रमों या संस्थाओं, वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थाओं, विद्युत् उत्पादन केन्द्रों, रिफायनरियों, धार्मिक महत्व के स्थानों, पुरातात्विक और विरासत स्थलों, हवाई अड्डों और हेलीपैडों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, शासकीय भवनों, मेट्रो नेटवर्क, स्वशासी निकायों, शासकीय संस्थापनाओं तथा केन्द्रीय तथा राज्य की संस्थाओं को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिये तथा निजी क्षेत्र की औद्योगिक स्थापनाओं को तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये राज्य के एक सशस्त्र बल का गठन करने तथा उसका विनियमन करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत के गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, २०१५ है.

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

- (क) "स्वशासी निकाय" से अभिप्रेत है स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली अथवा उस प्रकार कार्य करने की स्वतंत्रता रखने वाली कोई संस्था;
- (ख) "संज्ञेय अपराध" का वही अर्थ होगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा २ के खण्ड (ग) में इसके लिए दिया गया है;
- (ग) "महानिदेशक" से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन नियुक्त बल का महानिदेशक;
- (घ) "बल का भरती किया गया सदस्य" से अभिप्रेत है अवर अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी का, बल का कोई अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी या कोई अन्य सदस्य;
- (ङ) "बल" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल;
- (च) "सरकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार;
- (छ) "औद्योगिक स्थापना" से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा ३ के अधीन यथापरिभाषित कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई कंपनी या भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (१९३२ का ९) की धारा ५९ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई फर्म जो कि किसी उद्योग या किसी व्यापार, कारबार या सेवा में लगी हुई है;
- (ज) "औद्योगिक उपक्रम" से अभिप्रेत है किसी अनुसूचित उद्योग से संबंधित कोई उपक्रम और इसमें सम्मिलित है कोई उपक्रम जो किसी ऐसे अन्य उद्योग या किसी व्यापार, कारबार या सेवा में लगा है

जो कि संसद् या राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किए जा सकते हों;

(झ) “सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम” से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जो—

- (एक) कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा २ के खण्ड (४५) में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी द्वारा;
- (दो) राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी ऐसे निगम द्वारा, जो कि सरकार द्वारा नियंत्रित हो तथा जिसका प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता हो, धारित, नियंत्रित हो अथवा उनके द्वारा उसका प्रबंध किया जाता हो.
- (ज) “संयुक्त उपक्रम” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा किसी निजी औद्योगिक उपक्रम के साथ संयुक्त रूप से हाथ में लिया गया कोई उपक्रम;
- (ट) “किसी औद्योगिक उपक्रम के संबंध में “प्रबंध निदेशक” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति (चाहे वह प्रबंध अभिकर्ता, महाप्रबंधक, प्रबंधक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) जिसका उस उपक्रम के कार्यों पर नियंत्रण हो;
- (ठ) “बल का सदस्य” से अभिप्रेत हैं इस अधिनियम के अधीन बल में नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (ड) “परिनियोजन का स्थान” से अभिप्रेत हैं औद्योगिक स्थापनाएं, औद्योगिक उपक्रम, निजी औद्योगिक उपक्रम या संस्थाएं, वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थाएं, विद्युत् उत्पादन केन्द्र, पारेषण और वितरण कंपनी, रिफायनरी, धार्मिक महत्व के स्थान, पुरातात्विक और विरासत स्थल, हवाई अड्डे व हेलीपैड, राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग, सरकारी भवन, मेट्रो नेटवर्क, स्वशासी निकाय, केन्द्र और राज्य की संस्थाएं, सामरिक महत्व के अत्यावश्यक संस्थापन इत्यादि, जिनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बल को परिनियोजित किया जा सकेगा;
- (ढ) “विहित” से अभिप्रेत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;
- (ण) निजी औद्योगिक उपक्रम” से अभिप्रेत है कोई ऐसा उद्योग जो केन्द्रीय या राज्य सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित, नियंत्रित हो या उसके द्वारा उसका प्रबंध किया जाता हो या सार्वजनिक क्षेत्र में का कोई औद्योगिक उपक्रम;
- (त) “अनुसूचित उद्योग” से अभिप्रेत है उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६५) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ कोई उद्योग;
- (थ) “सामरिक महत्व के अत्यावश्यक संस्थापन” से अभिप्रेत है विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले समस्त ऐसे अत्यावश्यक और अति संवेदनशील स्थल अथवा क्षेत्र जिन्हें कि समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (द) “अधीनस्थ अधिकारी” से अभिप्रेत है निरीक्षक, उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक के रूप में बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (ध) “पर्यवेक्षण अधिकारी” से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी और इसमें सम्मिलित है बल के पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी;
- (न) “अवर अधिकारी” से अभिप्रेत है हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के रूप में बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति.

३. (१) राज्य सरकार द्वारा, परिनियोजन के स्थान के संरक्षण और सुरक्षा के लिए तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं, औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से ज्ञात एक सशस्त्र बल गठित और संधारित किया जाएगा।

बल का गठन.

(२) बल में उतने पर्यवेक्षण अधिकारी अंतर्विष्ट होंगे जितने के विहित किए जाएं और वे ऐसा वेतन और अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो कि विहित किया जाए:

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात भारतीय पुलिस सेवा के सदस्यों के वेतन भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों को लागू नहीं होगी.

(३) बल का मुख्यालय भोपाल में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर होगा जिसे कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए.

४. (१) सरकार, किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक नियुक्त करेगी तथा उतने अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी जैसे अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, कमाण्डेंट डिप्टी कमाण्डेंट, असिस्टेंट कमाण्डेंट नियुक्त कर सकेगी जितने की आवश्यक समझे जाएं.

पर्यवेक्षण अधि-
कारियों की नियुक्ति
तथा शक्तियां.

(२) महानिदेशक तथा इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कि विहित किए जाएं.

५. महानिदेशक या ऐसा पर्यवेक्षण अधिकारी जिसे कि सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, बल के सदस्यों को भर्ती करेगा.

बल के नामांकित
सदस्यों की नियुक्ति.

६. (१) बल का भर्ती किया गया प्रत्येक सदस्य, उसकी नियुक्ति पर, विहित प्ररूप में महानिदेशक अथवा ऐसे अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा से, जिसे कि महानिदेशक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करने वाले व्यक्ति में बल में भर्ती किए गए सदस्य की शक्तियां निहित हो जाएंगी.

बल के सदस्यों के
प्रमाण-पत्र.

(२) ऐसे प्रमाण-पत्र का उस स्थिति में स्वतः ही अवसान हो जाएगा जबकि वह व्यक्ति जिसके कि पक्ष में यह जारी किया गया हो, किसी भी कारण से बल का भर्ती किया गया सदस्य नहीं रह जाता है.

७. (१) महानिदेशक, सरकार के सर्वोपरि नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए बल का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होगा. वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कि विहित किए जाएं.

बल का अधीक्षण
तथा प्रशासन.

(२) उपधारा (१) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए बल का प्रशासन, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जैसी कि विहित की जाएं, अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक अथवा कमाण्डेंट, डिप्टी कमाण्डेंट, और असिस्टेंट कमाण्डेंट द्वारा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा और राज्य में बल के परिनियोजन के स्थानों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया भारसाधक अधिकारी ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर कार्य करेगा जो कि विहित किए जाएं और ऐसे निदेशों के अध्वधीन रहते हुए, जैसे के सरकार अथवा महानिदेशक द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, अपने कृत्यों का निर्वहन, परिनियोजन के ऐसे स्थान के भारसाधक प्राधिकारी के साथ सामंजस्य बना कर करेगा.

८. बल के प्रत्येक अधिकारी तथा सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह —

बल के सदस्यों के
कर्तव्य.

(एक) अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसे दिए गए समस्त विधिपूर्ण आदेशों का पालन तथा निष्पादन करे;

- (दो) परिनियोजन के स्थान तथा उससे संलग्न किन्हीं संस्थापनों के परिसरों, उनकी स्थापनाओं तथा आस्तियों का संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा करना;
- (तीन) खण्ड (दो) में यथाविनिर्दिष्ट परिनियोजन के स्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों का संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा करना;
- (चार) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट परिनियोजन के स्थान तथा खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के संरक्षण तथा सुरक्षा में सहायक कोई अन्य कार्य करना;
- (पांच) परिनियोजन के स्थान और उसके आसपास कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण स्थानीय पुलिस बल को, उसके आने पर सहयोग और सहायता प्रदान करना.

बल का परिनियोजन.

९. (१) सरकार के सामान्य निदेशों और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि विहित की जाएं, बल के प्रभारों की वसूली के अध्यक्षीन रहते हुए, महानिदेशक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह परिनियोजन के स्थान के भारसाधक अधिकारी से, उसकी आवश्यकता को दर्शाते हुए, इस निमित्त अनुरोध प्राप्त होने पर, उतनी संख्या में, जितनी कि महानिदेशक उसके तथा उससे संलग्न किन्हीं संस्थापनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे, बल के सदस्यों को परिनियोजित कर सकेगा और इस प्रकार परिनियोजित बल का सदस्य महानिदेशक अथवा उसके निमित्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा प्राधिकारी के अधिकार के अधीन रहेगा:

परन्तु उस दशा में, जहां कि कोई स्थापना, संस्था, स्वशासी निकाय, उपक्रम, सामरिक महत्व के या अत्यावश्यक संस्थापन किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित हों अथवा उसके द्वारा उनका प्रबन्ध किया जाता हो, जिसमें कि राज्य सरकार का कोई हित न हो, वहां सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

(२) यदि महानिदेशक का यह मत है कि उपधारा (१) के अधीन परिनियोजन के किसी स्थान के सम्बन्ध में बल के सदस्यों के परिनियोजन की आवश्यकता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, तो वह इस प्रकार परिनियोजित बल के सदस्यों को, उसके लिए कोई कारण बताए बिना, वापस बुला सकेगा.

(३) बल का प्रत्येक सदस्य जब वह अपनी परिनियोजन की कालावधि के दौरान किसी ऐसी स्थापना, संस्था, स्वशासी निकाय, उपक्रम, सामरिक महत्व के अथवा अत्यावश्यक संस्थापनों में अपने कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो जो किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित हों अथवा उसके द्वारा उनका प्रबन्ध किया जाता हो, जिसमें सरकार का कोई हित न हो, इस अधिनियम के अधीन उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अधीन रहेगा जिनके अधीन वह तब होता जबकि वह सरकार की किसी स्थापना, संस्था, स्वशासी निकाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा सामरिक महत्व के तथा अत्यावश्यक संस्थापनों के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता.

वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति.

- १० (१) बल का कोई भी सदस्य वारन्ट के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा,—

(एक) जो धारा ८ के खण्ड (चार) में विनिर्दिष्ट यथास्थिति, किसी कर्मचारी या अधिकारी को या उसे या बल के किसी अन्य सदस्य को उसके ऐसे कर्मचारी के रूप में कर्तव्य के निर्वहन में या ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य के निष्पादन में, या उसे ऐसे सदस्य के रूप में कर्तव्य के निर्वहन से रोकने या भयभीत करने के आशय से या उसे ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन के परिणामस्वरूप किसी कार्य को करने अथवा करने का प्रयास करने में स्वेच्छया उपहति कारित करता है या स्वेच्छया उपहति कारित करने का प्रयास करता है, या सदोष अवरोध करता है, या सदोष अवरोध करने का प्रयास करता है, या हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है या उपयोग करने की धमकी देता है या प्रयास करता है;

- (दो) जो किसी संज्ञेय अपराध को कारित किए जाने में संबद्ध रह चुका हो, अथवा जिसके विरुद्ध इस प्रकार संबद्ध रहने का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो या जो ऐसी परिस्थितियों के अधीन अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है जिससे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसी पूर्वावधानियां किसी संज्ञेय अपराध को कारित करने की दृष्टि से, जिसका संबंध ऐसी संपत्ति से है, जो परिनियोजन के स्थान से संबंधित हो या उसमें विद्यमान हो;
- (तीन) जो कोई ऐसा संज्ञेय अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है जिसमें परिनियोजन के स्थान से संबंधित कोई कार्य करने में लगे हुए किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा अन्तर्वलित हो या खतरा अन्तर्वलित होने की संभावना हो.

(२) यदि कोई व्यक्ति परिनियोजन के स्थान के परिसरों में अतिचार करता हुआ पाया जाए तो उसे किन्हीं ऐसी अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, बल के किसी सदस्य द्वारा ऐसे परिसरों से हटाया जा सकेगा.

११ (१) जब भी बल के किसी सदस्य को यह विश्वास करने का कारण हो कि परिनियोजन के स्थान में कोई ऐसा अपराध जो कि धारा १० में निर्दिष्ट किया गया है, कारित किया गया है या कारित किया जा रहा है और अपराधी को बच निकलने या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिए बिना तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह अपराधी को निरुद्ध कर सकेगा और उस व्यक्ति के सामान की तत्काल तलाशी ले सकेगा और यदि वह उचित समझे तो ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध कारित किया है, गिरफ्तार कर सकेगा.

वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति.

(२) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के तलाशियों से सम्बन्धित उपबंध इस धारा के अधीन तलाशियों को लागू होंगे.

१२. इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाला बल का कोई सदस्य, इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल किसी पुलिस अधिकारी के सुपुर्द करेगा और किसी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ जिनके कारण गिरफ्तारी की गई है, ऐसे व्यक्ति को निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा.

गिरफ्तारी के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.

१३. (१) उन साधारण निदेशों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो कि सरकार द्वारा जारी किए जाएं, महानिदेशक के लिए वह विधिपूर्ण होगा कि वह निजी क्षेत्र के किसी औद्योगिक स्थापन के प्रबन्ध संचालक से या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसे औद्योगिक स्थापन को, ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो कि विहित की जाए, सुरक्षा से संबंधित तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बल के सदस्यों को निदेश दे.

औद्योगिक स्थापनों को तकनीकी परामर्शी सेवाएं देने का उपबंध.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त फीस ऐसी रीति में, जैसी कि विहित कि जाए, संचित निधि में जमा की जाएगी.

१४. राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रत्येक सदस्य, उसकी नियुक्ति पर तथा जब तक कि वह बल का सदस्य बना रहता है, पुलिस अधिकारी समझा जाएगा और जब वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो अथवा उसके द्वारा वैसा निर्वहन किया जाना तात्पर्यित हो, तथा उन निबन्धनों, शर्तों तथा निबन्धनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो कि विहित किए जाएं, और जहां तक कि वे इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हों, उन्हें पुलिस अधिनियम, १८६१ (१८६१ का ५) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सम्यक् रूप से नामांकित पुलिस अधिकारी के समस्त विशेषाधिकार तथा संरक्षण प्राप्त होंगे और वे पुलिस अधिकारी के समान समस्त दायित्वों, शास्तियों और दण्ड के अध्यक्षीन होंगे.

औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों को पुलिस अधिकारियों के समान विशेषाधिकार तथा दायित्वों का होना.

सद्भावपूर्वक की गई
कार्रवाई का संरक्षण.

१५. बल के विरुद्ध या उसके किसी अधिकारी या सदस्य के विरुद्ध या बल के अथवा उसके किसी अधिकारी या सदस्य के आदेश या निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई वाद या अभियोजन ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अपराधों का संज्ञान.

१६. कोई भी न्यायालय, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना बल के किसी सदस्य के विरुद्ध, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कृत्य के सम्बन्ध में किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा.

बल के सदस्यों को
सदैव कर्तव्य पर
समझा जाना तथा
राज्य में तथा राज्य के
बाहर भी नियोजित
किया जा सकता.

१७. (१) बल का प्रत्येक सदस्य सदैव कर्तव्य पर समझा जाएगा और मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या राज्य के बाहर भी किसी भी समय, किसी भी स्थान पर नियोजित किया जा सकेगा.

(२) बल का कोई भी सदस्य स्वयं को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या कार्यालय में नहीं लगाएगा.

दण्ड और अपीलें.

१८. संविधान के अनुच्छेद ३११ तथा उन नियमों के, जो कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए, उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, पर्यवेक्षण अधिकारी—

(एक) बल के भर्ती किए गए किसी ऐसे सदस्य को, जिसे वह असावधान, अपने कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षावान या उसके लिए अनुपयुक्त समझता है, बर्खास्त कर सकेगा, हटा सकेगा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कर सकेगा या पंक्ति में अवनत कर सकेगा; या

(दो) बल के भर्ती किए गए किसी सदस्य को, जो अपने कर्तव्य का लापरवाहीपूर्ण या उपेक्षापूर्ण रीति में निर्वहन करता है या जो अपने स्वयं के किसी कार्य द्वारा उसके निर्वहन हेतु अनुपयुक्त हो जाता है, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दण्ड दे सकेगा, अर्थात् :—

(क) जुर्माना, जो सात दिन के वेतन से अनधिक किसी भी राशि तक का हो सकेगा, या वेतनमान में कमी करना;

परन्तु पर्यवेक्षण अधिकारी लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले विशेष कारणों से, सात दिन के वेतन से अधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा;

(ख) ड्रिल, अतिरिक्त पहरेदारी, असैनिक सेवा या कोई अन्य कार्य;

(ग) किसी विशिष्ट पद से हटाना या किसी विशेष परिलाभ से वंचित करना;

(घ) संचयी प्रभाव सहित या उसके बिना वेतनवृद्धि रोकना;

(ङ) पदोन्नति रोकना;

(च) परिनिंदा करना.

इस धारा के खण्ड (एक) या (दो) के अधीन दिए गए किसी आदेश से व्यथित बल का भर्ती किया गया कोई सदस्य उस तारीख से, जिसको कि उसे आदेश संसूचित हुआ है, तीस दिन के भीतर उस आदेश के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा. विहित प्राधिकारी, किसी अपील का निराकरण करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि विहित की जाए:

परन्तु विहित प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय-सीमा में अपील प्रस्तुत न किए जाने के पर्याप्त कारण थे, तीस दिन की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

१९(१) बल का कोई भी सदस्य, सरकार या विहित प्राधिकारी की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना,—

संगम इत्यादि बनाने के अधिकार के विषय में निर्बंधन।

(क) किसी भी व्यापार संघ, मजदूर संघ, राजनैतिक दल अथवा व्यापार संघों, मजदूर संघों अथवा राजनैतिक दलों के महासंघ का सदस्य नहीं होगा अथवा उनसे किसी भी रूप में सहयुक्त नहीं होगा; या

(ख) किसी अन्य सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन का, जो कि बल के भाग के रूप में मान्यताप्राप्त नहीं है या जो विशुद्ध रूप से सामाजिक, आमोद प्रमोद संबंधी या धार्मिक प्रकृति का नहीं है, सदस्य नहीं बन सकेगा या उससे किसी अन्य प्रकार से सहयुक्त नहीं हो सकेगा; या

स्पष्टीकरण—यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन विशुद्ध रूप से सामाजिक, आमोद प्रमोद संबंधी या धार्मिक प्रकृति का है या नहीं तो ऐसी दशा में सरकार का विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(ग) किसी भी प्रेस से संपर्क नहीं करेगा या कोई भी पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेज प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा, सिवाय तब के जबकि ऐसी संसूचना या प्रकाशन उसके वास्तविक कर्तव्य के निर्वहन के लिए हो, या वह बिल्कुल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की हो।

(२) बल का कोई भी सदस्य किसी भी राजनैतिक प्रयोजन के लिए किसी सम्मेलन या प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या उसे संबोधित नहीं करेगा।

२०. बल के किसी सदस्य की, उसके पद से निलंबित हो जाने के कारण सदस्यता समाप्त नहीं होगी और वह उस कालावधि के दौरान भी उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अध्वधीन होगा जिनके अध्वधीन वह कर्तव्यारूढ़ होने की दशा में होता।

निलंबन के दौरान बल के सदस्यों के उत्तरदायित्व।

२१(१) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी कारण से भर्ती किया गया बल का सदस्य नहीं रह जाता है, अपना नियुक्ति प्रमाण-पत्र, आयुध, साजसज्जा, वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं, जो उसे बल के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का पालन करने के लिए दी गई हों, किसी ऐसे पर्यवेक्षक अधिकारी को तत्काल अभ्यर्पित कर देगा जो उन्हें प्राप्त करने के लिए सशक्त हो।

बल का सदस्य न रह गए व्यक्तियों द्वारा प्रमाण-पत्र, आयुध आदि का अभ्यर्पण।

(२) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) में यथा अपेक्षित वस्तुओं का अभ्यर्पण करने में जानबूझकर उपेक्षा करता है अथवा अभ्यर्पण करने से इंकार करता है, आर्थिक फायदों के समपहरण और विधि के अधीन अभियोजन का दायी होगा।

(३) इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसी वस्तु को लागू नहीं समझी जाएगी जो कि महानिदेशक के आदेशों के अधीन, उस व्यक्ति की, जिसे वह दी गई हो, संपत्ति हो गई हो।

२२. पुलिस (अप्रीति उद्दीपन) अधिनियम, १९२२ (१९२२ का २२) बल के सदस्यों को उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि वह पुलिस बल के सदस्यों को लागू होता है।

१९२२ के अधिनियम क्रमांक २२ का बल के सदस्यों को लागू होना।

२३. मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ (१९३६ का ४) अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) अथवा कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) में अंतर्विष्ट कोई भी बात, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित उसके उपबंधों के सिवाय बल के सदस्यों को लागू नहीं होगी।

कतिपय अधिनियमों का बल के सदस्यों पर लागू न होना।

नियम बनाने की शक्ति.

२४(१) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे,—

- (क) बल के सदस्यों के वर्गों, पंक्तियों, ग्रेडों, तमगों, वेतन और पारिश्रमिक का तथा बल में उनकी सेवा शर्तों का विनियमन;
- (ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कृत्य करने के लिए प्राधिकृत बल के सदस्यों की शक्तियों और कर्तव्यों का विनियमन;
- (ग) बल के सदस्यों के लिए सेवा की कालावधि नियत करना;
- (घ) बल के सदस्यों को दिए जाने वाले आयुध, साजसज्जा, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रकार और उनकी मात्रा विहित करना;
- (ङ) बल के सदस्यों के निवास स्थान विहित करना;
- (च) बल के प्रशासन से संबद्ध किसी प्रयोजन के लिए किसी निधि की संस्थापना, उसका प्रबंध और विनियमन;
- (छ) दण्डों का विनियमन और वे प्राधिकारी विहित करना जिन्हें दण्ड के, अथवा जुर्माने या अन्य दण्ड के परिहार के आदेशों से अपीलें की जाएंगी और ऐसी अपीलों को निपटाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (ज) वे निबंधन तथा शर्तें जिनके कि अध्याधीन रहते हुए बल के सदस्यों को धारा ९ के अधीन परिनियोजित किया जा सकेगा और उसके लिए प्रभार;
- (झ) अग्न्यायुधों का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश विहित करना;
- (ञ) किराए पर लेने वाली संस्थाओं के साथ संबंध बनाए रखने के लिए मानक विहित करना.

(३) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

२५. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्र. 4631-282-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 2015 (क्रमांक 19, सन् 2015)का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 19 OF 2015

THE MADHYA PRADESH AUDYOGIK SURAKSHA BAL ADHINIYAM, 2015

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent and commencement
2. Definitions
3. Constitution of the Force
4. Appointment and powers of supervisory officers
5. Appointment of enrolled members of the Force
6. Certificates of members of the Force
7. Superintendence and administration of the Force
8. Duties of members of the Force
9. Deployment of the Force
10. Power to arrest without warrant
11. Power to search without warrant
12. Procedure to be followed after arrest
13. Provision for technical consultancy services to industrial establishments
14. Members of the State Industrial Security Force to have same privileges and liabilities as a police officer
15. Protection of action taken in good faith
16. Cognizance of offences
17. Members of the Force to be considered always on duty and liable to be deployed anywhere in the State and outside also.
18. Punishments and appeals
19. Restrictions respecting right to form associations etc.
20. Responsibilities of member of the Force during suspension
21. Surrender of certificate, arms, etc. by persons ceasing to be members of the Force
22. Application of Act No. 22 of 1922 to the members of the Force
23. Certain Acts not to apply to the members of the Force
24. Power to make rules
25. Power to remove difficulties

MADHYA PRADESH ACT

No. 19 OF 2015

THE MADHYA PRADESH AUDHYOGIK SURAKSHA BAL ADHINIYAM, 2015

[Received the assent of the Governor on the 24th August, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th September, 2015].

An Act to provide for the constitution and regulation of an armed force of the State for protection and security of industrial establishments, industrial undertakings, private industrial undertakings or institutions, commercial and financial institutions, power generating stations, refineries, places of religious importance, archaeological and heritage sites airports and helipads, National or State Highways, Government buildings, metro network, autonomous bodies, Government installations, Central and State institutions and to provide technical consultancy services to industrial establishments in the private sector and for matters connected therewith and ancidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Audyogik Suraksha Bal Adhiniyam, 2015.
- (2) It extends to whole of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "autonomous body" means an institution acting independently or having the freedom to do so;
 - (b) "cognizable offence" has the meaning assigned to it in clause (c) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974);
 - (c) "Director General" means the Director General of the Force appointed under Section 4;
 - (d) "enrolled member of the Force" means any subordinate officer, under officer or any other member of the Force of a rank not lower than that of an under officer;
 - (e) "Force" means the State Industrial Security Force constituted under Section 3;
 - (f) "Government" means the State Government;
 - (g) "industrial establishment" means and industrial undertaking or a company as defined under Section 3 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) or a firm registered under Section 59 of the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932), which is engaged in any industry or in any trade, business or service;
 - (h) "industrial undertaking" means an undertaking pertaining to a scheduled industry and includes an undertaking engaged in any other industry or in any trade, business or service which may be regulated by law made by the Parliament or Legislature of the State;

- (i) "industrial undertaking in public sector" means an industrial undertaking owned, controlled or managed by—
- (i) a Government company as defined in clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013);
- (ii) a corporation established by or under a State Act, which is controlled or managed by the Government.
- (j) "joint venture" means a venture jointly undertaken by the State Government with a private industrial undertaking;
- (k) "Managing Director" in relation to an industrial undertaking means, the person (whether called a Managing Agent, General Manager, Manager, Chief Executive Officer or by any other name) who exercises control over the affairs of that undertaking;
- (l) "member of the Force" means a person appointed to the Force under this Act;
- (m) "place of deployment" means industrial establishments, industrial undertakings, private industrial undertakings or institutions, commercial and financial institutions, power generating stations, transmission and distribution company, refinery, places of religious importance, archaeological and heritage sites, airports and helipads, National or State Highways, Government buildings, metro network, autonomous bodies, Central and State institutions, strategic vital installations etc. for whose protection and security the Force may be deployed under the provisions of this Act;
- (n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (o) "private industrial undertaking" means an industry owned, controlled or managed by a person other than the Central or State Government or any industrial undertaking in public sector;
- (p) "scheduled industry" means any industry engaged in the manufacture or production of the articles mentioned in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);
- (q) "strategic and vital installation" means all such essential and vulnerable points or areas requiring special protection, as may from time to time be specified by the Government;
- (r) "subordinate officer" means a person appointed to the Force as an Inspector, a Sub-Inspector or an Assistant Sub-Inspector;
- (s) "supervisory officer" means any officer appointed under Section 4 and includes any other officer appointed by the State Government as a supervisory officer of the Force;
- (t) "Under Officer" means a person appointed to the Force as a Head Constable or Constable.

3. (1) There shall be constituted and maintained by the State Government an armed force to be called the State Industrial Security Force for the protection and security of place of deployment and to perform such other duties as may be entrusted to it by the State Government.

Constitution of the Force.

(2) The Force shall consist of such number of supervisory officers and enrolled members who shall receive such pay and other remuneration as may be prescribed:

Provided that nothing in this sub-section apply to the pay, allowances and other service conditions of members of the Indian Police Service.

(3) The headquarters of the Force shall be at Bhopal or at such other place as may be specified by the Government from time to time.

Appointment and powers of supervisory officers.

4. (1) The Government shall appoint a person to be the Director General of the Force and may also appoint other supervisory officers such as Additional Director General, Inspector General, Deputy Inspector General, Assistant Inspector General, Commandant, Deputy Commandant and Assistant Commandant as considered necessary.

(2) The Director General and every other supervisory officer so appointed, shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

Appointment of enrolled members of the Force.

5. The Director General or such other supervisory officers as may be authorized by the Government shall enrol members of the Force in such manner as may be prescribed.

Certificates of members of the Force.

6. (1) Every enrolled member of the Force shall receive on his appointment a certificate in the form prescribed, under the seal of the Director General or such other supervisory officer as the Director General may specify in this behalf and the person holding such certificate shall be vested with the powers of an enrolled member of the Force.

(2) Such certificate shall automatically expire whenever the person in whose favour it is issued, ceases for any reason, to be an enrolled member of the Force.

Superintendence and administration of the Force.

7. (1) The Director General shall be the principal administrative officer of the Force subject to overall control of the Government. He shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the administration of the Force within such local limits as may be prescribed, shall be carried on by the Additional Director General, Inspector General, Deputy Inspector General, Assistant Inspector General or Commandant, Deputy Commandant and Assistant Commandant in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder and every supervisory officer placed in charge of the protection and security of places of deployment in the State, shall function on such terms and conditions as may be prescribed and shall subject to any direction that may be given by the Government or the Director General in this behalf, discharge his functions in co-ordination with the authority in charge of such place of deployment.

Duties of members of the Force.

8. It shall be the duty of every officer and member of the Force :—

- (i) to obey and execute all orders lawfully issued to him by his superior officer;
- (ii) to protect and safeguard the premises, their establishments and assets of the place of deployment and any installations attached thereto;
- (iii) to protect and safeguard the employees and officers of the place of deployment as referred to in clause (ii);
- (iv) to do any other act conducive to the protection and security of the place of deployment referred to in clause (ii) and the employees and officers referred to in clause (iii);
- (v) to aid and assist the local police force, on its arrival consequent to a law and order situation in and around the place of deployment.

9. (1) Subject to any general direction of the Government and the recovery of charges of the force on such terms and conditions as may be prescribed, it shall be lawful for the Director General on a request received in this behalf from the authority in charge of the place of deployment showing the necessity thereof, to deploy such number of the members of the Force as the Director General may consider necessary for the protection and security thereof and any installations attached thereto and the member of the Force so deployed shall be under the charge of such officer or authority as specified by the Director General or any other officer on his behalf:

Deployment of the Force.

Provided that in the case of an establishment, institution, autonomous body, undertaking, strategic or vital installation controlled or managed by a Company in which the State Government does not have an interest, no such request shall be considered without the approval of the Government.

(2) If the Director General is of the opinion that the circumstances necessitating the deployment of the members of the Force in relation to a place of deployment under sub-section (1) have ceased to exist, he may withdraw the members of the Force so deployed without assigning any reason therefor.

(3) Every member of the Force while discharging his functions during the period of deployment in an establishment, institution, autonomous body, undertaking, strategic or vital installation controlled or managed by a Company in which the Government does not have an interest, shall exercise the same powers and be subject to the same responsibilities, discipline and penalties under this Act as he would have been, if he had been discharging those duties in relation to an establishment, an institution, an autonomous body and industrial undertaking or strategic and vital installations of the Government.

10. (1) Any member of the Force may without a warrant, arrest any person :—

Power to arrest without warrant

- (i) who voluntarily causes hurt to or attempts voluntarily to cause hurt to, or wrongfully restrains or attempts wrongfully to restrain or assaults, or threatens to assault, or uses, or threatens or attempts to use criminal force to any employee or officer referred to in clause (iv) of Section 8, or to him or any other member of the Force in discharge of his duty as such employee or in execution of his duty as such member, as the case may be or with intent to prevent or to deter him from discharging his duty as such member or in consequence of anything done or attempted to be done by him in the lawful discharge of his duty as such member;
- (ii) who has been concerned in, or against whom a reasonable suspicion exists of his having been concerned in commission of a cognizable offence or who is found taking precautions to conceal his presence under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with a view to committing a cognizable offence which relates to property belonging to, or existing in the place of deployment;
- (iii) who commits or attempts to commit a cognizable offence which involves or which is likely to involve danger to the life of any person engaged in carrying on any work relating to the place of deployment.

(2) If any person is found trespassing on the premises of the place of deployment he may, without prejudice to any other proceedings which may be taken against him, be removed from such premises by any member of the Force.

11. (1) Whenever any member of the Force, has reason to believe that any such offence as is referred to in Section 10 has been or is being committed in the place of deployment and that a search warrant cannot be obtained without affording the offender an opportunity of escaping or concealing evidence of the offence, he may detain the offender and search his person and belongings forthwith and if he thinks proper, arrest any person whom he has reason to believe to have committed the offence.

Power to search without warrant.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) relating to searches shall apply to searches under this section.

Procedure to be followed after arrest.

12. Any member of the Force making an arrest under this Act immediately make over the person so arrested to a police officer and in the absence of a police officer, take such person or cause him to be taken to the nearest police station together with a report of the circumstances occasioning the arrest.

Provision for technical consultancy services to industrial establishments.

13. (1) Subject to any general direction which may be issued by the Government, it shall be lawful for the Director General on a request received from the Managing Director of any industrial establishment in the private sector or any other person authorized by him in this behalf, to direct the members of the Force to provide technical consultancy services relating to security, to such industrial establishment in such manner and on payment of such fee as may be prescribed.

(2) The fee received under sub-section (1) shall be credited to the Consolidated Fund in such manner as may be prescribed.

Members of the State Industrial Security Force to have same privileges and liabilities as a police officer.

14. Every member of the State Industrial Security Force shall upon his appointment and as long as he continues to be a member thereof, be deemed to be a police officer and subject to any terms conditions and restrictions as may be prescribed, to have and be subject to, in so far as they are not inconsistent with any provision of this Act or any rules made thereunder, all the privileges and protection and all the liabilities, penalties, punishments as a police officer duly enrolled is by virtue of the Police Act, 1861 (V of 1861), or any other law for the time being in force while discharging or purporting to discharge his duties under this Act and the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

15. No suit or prosecution shall be entertained by any Court against the Force or against any officer or member thereof or against any person acting under the order or direction of the Force or any officer or member thereof for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.

Cognizance of offence.

16. No court shall take cognizance of an offence against any member of the Force with regard to any act done by him while discharging or purporting to act in the discharge of his duty except with the prior sanction of the Government.

Members of the force to be considered as always on duty and liable to be employed anywhere in the State and outside also.

17. (1) Every member of the Force shall be considered to be always on duty and shall, at any time, be liable to be employed at any place within the State of Madhya Pradesh and outside also.

(2) No member of the Force shall engage himself in any employment or office other than his duties under this Act.

Punishments and appeals.

18. Subject to the provisions of article 311 of the Constitution and to such rules as the State Government may make under this Act, supervisory officer may—

- (i) dismiss, remove, order compulsory retirement or reduce in rank any enrolled member of the Force, whom he thinks remiss or negligent in the discharge of his duty, or unfit for the same; or
- (ii) award any one or more of the following punishments to any enrolled member of the Force who discharges his duty in a careless or negligent manner, or who by any act of his own renders himself unfit for the discharge thereof, namely :—

- (a) fine, which may extend to any amount not exceeding seven days' pay or reduction in pay scale:

Provided that the supervisory officer may, for special reasons to be recorded in writing, impose a fine exceeding seven days' pay;

- (b) drill, extra guard, fatigue or other duty;
- (c) removal from any office of distinction or deprivation of any special emolument;
- (d) withholding of increment of pay with or without cumulative effect;
- (e) withholding of promotion;
- (f) censure.

Any enrolled member of the Force aggrieved by an order made under clause (i) or (ii) of this section may, within thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal against the order to such authority as may be prescribed. In disposing of an appeal, the prescribed authority shall follow such procedure as may be prescribed:

Provided that the prescribed authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

19. (1) No member of the Force shall without the previous sanction in writing of the Government or of the prescribed authority:

Restrictions respecting right to form associations etc.

- (a) be a member of, or be associated in any way with any trade union, labour union, political party or with any association or confederation of trade unions, labour unions or political parties; or
- (b) be a member of, or be associated in any way with, any other society, institution, association or organization that is not recognized as part of the Force or is not of a purely social, recreational or religious nature; or

Explanation.—If any question arises as to whether any society, institution, association or organization is of purely social, recreational or religious nature under clause (b) of this sub-section, the decision of the Government thereon shall be final.

- (c) communicate with the press or publish or cause to be published any book, letter or other document except where such communication or publication is in the bonafide discharge of his duties or is of a purely literary, artistic or scientific character.

(2) No member of the Force shall participate in or address, any meeting or take part in any demonstration for any political purpose.

20. A member of the Force shall not by reason of his suspension from office, cease to be a member of the Force and he shall, during that period, be subject to the same responsibilities, discipline and penalties as he would have been, if he was on duty.

Responsibilities of member of the Force during suspension.

21. (1) Every person who for any reason ceases to be an enrolled member of the Force, shall forthwith surrender to any supervisory officer empowered to receive the same, his certificate of appointment, the arms, accoutrements, clothing and other articles which had been furnished to him for the performance of his duties as an enrolled member of the Force.

Surrender of certificate, arms etc. by persons ceasing to be members of the Force.

(2) Any person who wilfully neglects or refuses to surrender the articles as required by sub-section (1) shall be liable for forfeiture of financial benefits and prosecution under the law.

(3) Nothing in this section shall be deemed to apply to any article which under the orders of the Director General, has become the property of the person to whom the same was furnished.

Application of Act No. 22 of 1922 to the members of the Force.

22. The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 (No. 22 of 1922) shall apply to members of the Force as it applies to members of the Police Force.

Certain Acts not to apply to the members of the Force.

23. Nothing contained in the Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936) or the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) or the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), except the provisions thereof relating to health and safety, shall apply to members of the Force.

Power to make rules.

24. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for,—

- (a) regulating the classes, ranks, grades, insignia, pay and remuneration of members of the Force and their conditions of service;
- (b) regulating the powers and duties of members of the Force authorized to exercise any function by or under this Act;
- (c) fixing the period of service for members of the Force;
- (d) prescribing the description and quantity of arms, accoutrements, clothing and other necessary articles to be furnished to the members of the Force;
- (e) prescribing the places of residence of members of the Force;
- (f) institution, management and regulation of any fund for any purpose connected with the administration of the Force;
- (g) regulating the punishments and prescribing authorities to whom appeals may be preferred from orders of punishment, or remission of fines or other punishments and the procedure to be followed for the disposal of such appeals;
- (h) the terms and conditions subject to which members of the Force may be deployed under section 9 and the charges therefore;
- (i) prescribing the guidelines for use of fire arms;
- (j) prescribing the norms to maintain relationship with hiring institutions.

(3) Every rule made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Legislative Assembly of the State.

Power to remove difficulties.

25. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.